Reporters Required!
For
Delhi, Haryana, UP, Ludhiana, Shimla, Bihar, Jammu, Jaipur Amritsar, Bathinda,
Call/WhatsApp:
+91-9157875000
+91-9041488440
Email:
azadvaani65@gmail.com

Monthly Hindi/English Newspaper
Published from SAS Nagar (Mohali)

Azad वाणी

NEWS • VIEWS • ANALYSIS

RNI No. PBBIL/26/A0779

Wed - 10 Jun - 2026 | Year - 01 | Issue - 65 | Page - 01 | Rs. - 5 | www.azadvaani.com

माई भागो एएफपीआई की कैडेट दीक्षा शर्मा का इंडियन नेवल अकादमी के लिए चयन

चंडीगढ़, 10 जून: पंजाब की बेटियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। माई भागो आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट (एएफपीआई) की लेडी कैडेट दीक्षा शर्मा का चयन प्रतिष्ठित इंडियन नेवल अकादमी में प्री-कमीशन प्रशिक्षण के लिए हुआ है। वह इस महीने के अंत तक अकादमी में प्रशिक्षण के लिए शामिल होंगी।

मोहाली के बस मालिक एवं संचालक दया कृष्ण शर्मा की पुत्री दीक्षा शर्मा का चयन भारतीय नौसेना की शिक्षा शाखा में हुआ है।

हवाला नेटवर्क पर पंजाब पुलिस का बड़ा प्रहार, तीन दिवसीय विशेष अभियान शुरू

चंडीगढ़, 10 जून: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर पंजाब पुलिस ने 'युद्ध नशों विरुद्ध' अभियान के तहत अवैध हवाला कारोबारियों के खिलाफ तीन दिवसीय राज्यस्तरीय विशेष अभियान शुरू किया है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि इसका उद्देश्य नशा तस्करी से जुड़े वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करना और ड्रग मनी के लेन-देन पर रोक लगाना है।

उन्होंने बताया कि अभियान के तहत अब तक 73 हवाला संचालकों को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा लगभग 10 करोड़ रुपये की हवाला राशि बरामद की गई है। वर्ष 2022 से अब तक एनडीपीएस एक्ट की धारा 68एफ के तहत 830 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियां फ्रीज की गई हैं, जबकि 1,727 से अधिक संपत्तियों की जब्ती को मंजूरी मिल चुकी है।

डीजीपी ने कहा कि 1 मार्च 2025 से अब तक नशा कारोबार से अर्जित 20 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध कमाई भी बरामद की गई है।

पंजाब कैबिनेट के बड़े फैसले: नीट अभ्यर्थियों को मुफ्त बस यात्रा, 1,169 सरकारी नौकरियां और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा

चंडीगढ़, 10 जून 2026। मुख्यमंत्री Bhagwant Singh Mann की अध्यक्षता में बुधवार को हुई पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में जनकल्याण, शिक्षा, रोजगार, आधारभूत ढांचे, स्वच्छ ऊर्जा और औद्योगिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य विद्यार्थियों को राहत देना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना, कचरा प्रबंधन को आधुनिक बनाना तथा राज्य में निवेश और उद्योगों को प्रोत्साहित करना है।

कैबिनेट ने पुनर्निर्धारित नीट-यूजी परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों और उनके एक सहयोगी के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा को मंजूरी दी है। उल्लेखनीय है कि 3 मई 2026 को प्रस्तावित नीट परीक्षा रद्द होने के बाद अब इसका आयोजन 21 जून को किया जाएगा। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए 20, 21 और 22 जून को पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी की बसों में परीक्षा केंद्रों तक आने-जाने के लिए निशुल्क यात्रा उपलब्ध होगी। अभ्यर्थियों को केवल अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा।

रोजगार सृजन को बढ़ावा देते हुए कैबिनेट ने स्कूल शिक्षा विभाग में लेक्चरर कैडर (ग्रुप-बी) के 1,013 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी दी है। इनमें बैकलॉग और नवसृजित पद भी शामिल हैं। साथ ही उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में एकमुश्त पांच वर्ष की छूट देने का भी निर्णय लिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी।

इसके अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग में 156 जूनियर इंजीनियरों की भर्ती को भी स्वीकृति दी गई है। इनमें 127 पद सिविल और 29 पद इलेक्ट्रिकल शाखा के हैं। इन पदों की भर्ती पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा की जाएगी।

सतत विकास और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पटियाला और जालंधर नगर निगमों में 100-100 टन प्रतिदिन क्षमता वाले गीले कचरे आधारित कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। ये परियोजनाएं कचरे के वैज्ञानिक निपटान, लैंडफिल पर दबाव कम करने, स्वच्छता सुधारने और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में सहायक होंगी।

मंत्रिमंडल ने पंजाब सिविल सेवा नियमों में संशोधन कर वरिष्ठता विवादों के समाधान का रास्ता भी साफ किया है। अब समान मेरिट और समान जन्मतिथि वाले उम्मीदवारों की वरिष्ठता न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों या ग्रेडिंग के आधार पर तय की जाएगी।

औद्योगिक विकास को गति देने के लिए औद्योगिक एवं व्यवसाय विकास नीति-2026 में भी संशोधन किए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत वित्तीय प्रोत्साहन केवल एमएसएमई तक सीमित न रहकर सभी मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को उपलब्ध होंगे। साथ ही अनुसंधान, नवाचार, औद्योगिक क्लस्टरों और पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। सरकार का विश्वास है कि ये सुधार पंजाब को निवेश और उद्योगों के लिए देश के सबसे आकर्षक राज्यों में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

पंजाब पुलिस ने लॉन्च किया अत्याधुनिक 'सांझ' सिटीजन पोर्टल, महिलाओं की सुरक्षा और जनसेवा को मिलेगी नई मजबूती

चंडीगढ़/जालंधर, 10 जून। मुख्यमंत्री Bhagwant Singh Mann के नागरिक-केंद्रित और तकनीक आधारित पुलिसिंग के विजन को आगे बढ़ाते हुए पंजाब पुलिस ने जनसेवा और पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) Gaurav Yadav ने बुधवार को फिल्लौर स्थित ऐतिहासिक महाराजा रणजीत सिंह पंजाब पुलिस अकादमी में अत्याधुनिक 'सांझ' सिटीजन पोर्टल का शुभारंभ किया। 134 वर्ष पुरानी यह अकादमी पंजाब पुलिस की प्रमुख प्रशिक्षण संस्था है।

इस अवसर पर डीजीपी गौरव यादव ने विशेष डीजीपी कम्युनिटी अफेयर्स डिवीजन Gurpreet Kaur Deo के साथ महिलाओं की सुरक्षा और पुलिस सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 93 इलेक्ट्रिक स्कूटरों के बेड़े को भी हरी झंडी दिखाई। ये स्कूटर पंजाब पुलिस की महिला मित्र इकाइयों और महिला हेल्प डेस्क पर तैनात महिला पुलिस कर्मियों को उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उनकी कार्यक्षमता और पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

नया 'सांझ' सिटीजन पोर्टल राज्यभर में संचालित 530 से अधिक सांझ केंद्रों की सेवाओं को और अधिक आधुनिक बनाता है। पोर्टल में 14 नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं, जिनमें आधार आधारित ई-केवाईसी के माध्यम से पुलिस सत्यापन, क्यूआर कोड युक्त प्रमाणपत्र, डिजिटल भुगतान रसीदें, गुम हुए मोबाइल फोन की रिपोर्टिंग की सरल प्रक्रिया, पूरी तरह पेपरलेस किरायेदार सत्यापन प्रणाली, वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सेवाएं तथा पासपोर्ट सत्यापन अधिकारियों के लिए नागरिक फीडबैक प्रणाली शामिल हैं। फरवरी 2025 से अब तक इस फीडबैक प्रणाली के माध्यम से 90 हजार से अधिक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो चुकी हैं|

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि नया सांझ पोर्टल तकनीक, सुशासन और नागरिक हितों का उत्कृष्ट संगम है। इसके माध्यम से लोगों को पुलिस सेवाओं के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे तथा बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी। नागरिक अब घर बैठे कई महत्वपूर्ण सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने बताया कि पोर्टल को राष्ट्रीय डिजिटल पुलिस रिपॉजिटरी से भी जोड़ा गया है, जिससे वाहन एनओसी और लापता व्यक्तियों से संबंधित सूचनाओं का त्वरित आदान-प्रदान संभव होगा। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के पुलिस सत्यापन कार्यों के लिए एकीकृत पुलिस वेरिफिकेशन ऐप भी विकसित किया गया है।

कर्मचारियों, मजदूरों और संघर्षरत परिवारों की समस्याओं का होगा समाधान, वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश

चंडीगढ़, 10 जून 2026। पंजाब सरकार ने कर्मचारियों, मजदूरों और विभिन्न सामाजिक संगठनों की समस्याओं के समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए उनके प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित कीं। पंजाब के वित्त मंत्री Harpal Singh Cheema ने बुधवार को ग्राम पंचायत जल आपूर्ति पंप ऑपरेटर्स एसोसिएशन, मनरेगा कर्मचारी यूनियन तथा भूमि प्राप्ति संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी मांगों और चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की।

बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री Bhagwant Singh Mann के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के कर्मचारियों, मजदूरों और समाज के वंचित वर्गों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी जायज मांग या समस्या को नजरअंदाज नहीं करेगी और प्रत्येक मामले का गंभीरता से मूल्यांकन कर उचित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी समस्याओं और मांगों से संबंधित ज्ञापन वित्त मंत्री को सौंपे। इन ज्ञापनों में सेवा संबंधी मुद्दे, कार्यस्थल की चुनौतियां, प्रशासनिक अड़चनें, वित्तीय समस्याएं और अन्य कल्याणकारी मांगें शामिल थीं। वित्त मंत्री ने सभी पक्षों को ध्यानपूर्वक सुना और भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों पर सकारात्मक और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

हरपाल सिंह चीमा ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी उचित और वैध मांगों की निर्धारित समयसीमा के भीतर समीक्षा की जाए तथा आवश्यक कार्रवाई करते हुए उन्हें लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और श्रमिकों के हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इस दिशा में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में मौजूद विभिन्न विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने वित्त मंत्री को आश्वस्त किया कि संबंधित मामलों की फाइलों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिन मामलों में एक से अधिक विभागों की भागीदारी आवश्यक है, वहां अंतर-विभागीय मूल्यांकन प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाएगी ताकि निर्णय लेने में देरी न हो और प्रभावित लोगों को जल्द राहत मिल सके।

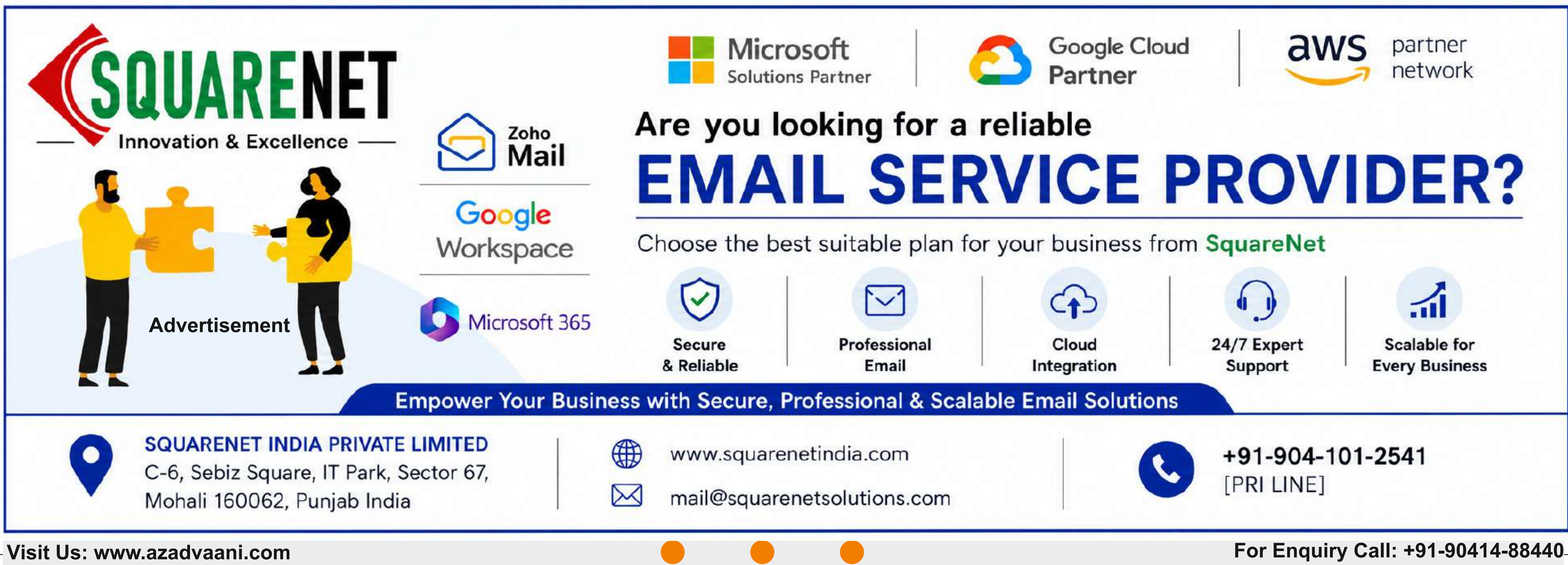

छत्तबीर चिड़ियाघर स्कूल क्लब बना पर्यावरण शिक्षा का मजबूत मंच, चार वर्षों में 4,850 स्कूल जुड़े, 4.21 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा

चंडीगढ़, 10 जून: वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण शिक्षा को नई दिशा देने के उद्देश्य से पंजाब के वन एवं वन्यजीव संरक्षण विभाग द्वारा संचालित छत्तबीर चिड़ियाघर स्कूल क्लब लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। वन एवं वन्यजीव संरक्षण मंत्री लाल चंद कटारूचक के नेतृत्व में चल रही इस पहल ने पिछले चार वर्षों के दौरान हजारों विद्यार्थियों को प्रकृति और जैव विविधता के संरक्षण के प्रति जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, छत्तबीर चिड़ियाघर स्कूल क्लब के साथ अब तक 4,850 स्कूल पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें 2,800 सरकारी तथा 2,050 निजी स्कूल शामिल हैं। यह संख्या दर्शाती है कि पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीवों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में व्यापक रुचि विकसित हुई है।

पिछले चार शैक्षणिक वर्षों के दौरान क्लब द्वारा आयोजित विभिन्न शैक्षणिक और जागरूकता कार्यक्रमों में कुल 4,21,079 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इन कार्यक्रमों में गाइडेड टूर, वन्यजीव संरक्षण कार्यशालाएं, प्रकृति अध्ययन शिविर, ईको-लर्निंग गतिविधियां तथा विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित विशेष सत्र शामिल रहे। इन गतिविधियों का उद्देश्य विद्यार्थियों को पुस्तकीय ज्ञान से आगे बढ़कर प्रकृति और वन्यजीवों के साथ प्रत्यक्ष रूप से जोड़ना था।

वर्ष 2022-23 में क्लब की गतिविधियों में 83,049 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। इसके बाद वर्ष 2023-24 में भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई और यह संख्या बढ़कर 1,37,011 तक पहुंच गई। यह लगभग 65 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है, जो कार्यक्रम की बढ़ती लोकप्रियता और प्रभावशीलता का प्रमाण है।

वर्ष 2024-25 में 1,11,731 विद्यार्थियों ने क्लब की गतिविधियों में हिस्सा लिया। वहीं वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के दौरान 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक 89,288 विद्यार्थी पहले ही विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हो चुके हैं। वर्ष 2023-24 की तुलना में भागीदारी में कुछ कमी आने के बावजूद विद्यार्थियों की संख्या लगातार उच्च स्तर पर बनी हुई है, जो इस पहल के प्रति लगातार बने विश्वास को दर्शाती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों की लगभग समान भागीदारी इस बात का संकेत है कि पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीवों के प्रति जागरूकता अब समाज के सभी वर्गों तक पहुंच रही है। यह पहल बच्चों में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने में सहायक सिद्ध हो रही है।

वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, छत्तबीर चिड़ियाघर स्कूल क्लब ने पारंपरिक चिड़ियाघर की अवधारणा को नई पहचान दी है। अब चिड़ियाघर केवल मनोरंजन या घूमने-फिरने के स्थान नहीं रह गए हैं, बल्कि वे "लिविंग क्लासरूम" के रूप में विकसित हो रहे हैं, जहां विद्यार्थी जीव-जंतुओं, उनके व्यवहार, प्राकृतिक आवास और संरक्षण संबंधी चुनौतियों को प्रत्यक्ष रूप से समझते हैं।

क्लब के माध्यम से विद्यार्थियों को वन्यजीवों की देखभाल, जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण संतुलन तथा सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी जाती है। इन गतिविधियों से बच्चों में पर्यावरणीय जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है और वे प्रकृति संरक्षण के महत्व को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं।

विभाग ने बताया कि सदस्य स्कूलों के लिए पूरे वर्ष पाठ्यक्रम आधारित गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इनमें प्रकृति भ्रमण, पोस्टर निर्माण प्रतियोगिताएं, वन्यजीव जागरूकता अभियान, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं, प्रकृति शिविर और इंटरैक्टिव लर्निंग सत्र शामिल हैं। इन कार्यक्रमों का संचालन वन्यजीव विशेषज्ञों, पर्यावरणविदों और अनुभवी शिक्षकों के सहयोग से किया जाता है।

वन मंत्री लाल चंद कटारूचक ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की संस्कृति को मजबूत करने के लिए बच्चों और युवाओं को प्रकृति से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को वन्यजीवों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूक बनाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। छत्तबीर चिड़ियाघर स्कूल क्लब इसी दिशा में एक सफल और प्रभावशाली पहल के रूप में उभर रहा है।

उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता में कमी और पर्यावरणीय चुनौतियों के इस दौर में ऐसी पहलें और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यदि बच्चों को प्रारंभिक स्तर पर ही पर्यावरण संरक्षण के महत्व से अवगत कराया जाए, तो वे भविष्य में प्रकृति के प्रति अधिक जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बन सकते हैं।

वन एवं वन्यजीव संरक्षण विभाग का मानना है कि छत्तबीर चिड़ियाघर स्कूल क्लब केवल एक शैक्षणिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक दीर्घकालिक निवेश है। यह पहल विद्यार्थियों को प्रकृति से जोड़ने, वन्यजीवों के प्रति सम्मान विकसित करने और उन्हें भविष्य के पर्यावरण संरक्षक के रूप में तैयार करने का कार्य कर रही है।

'गैंगस्टरों ते वार' के 141वें दिन 303 गिरफ्तार, 90 नशा तस्कर भी दबोचे

चंडीगढ़, 10 जून: पंजाब पुलिस ने राज्य को अपराधमुक्त बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे 'गैंगस्टरों ते वार' अभियान के 141वें दिन गैंगस्टरों के सहयोगियों के 577 ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान दो हथियार बरामद करते हुए 303 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही अभियान के तहत कुल गिरफ्तारियों की संख्या 35,662 तक पहुंच गई है।

पुलिस ने 123 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की, जबकि सात भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया। इसी दौरान 'युद्ध नशों विरुद्ध' अभियान के 466वें दिन 90 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 5.2 किलोग्राम हेरोइन, 35 किलोग्राम भुक्की, 360 नशीली गोलियां और 2,600 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई। अब तक कुल 67,662 नशा तस्करों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

पुरुषोत्तम मास में मां गंगा तट पर गूंज रही श्रीमद्भागवत कथा, उमड़ रही श्रद्धालुओं की आस्था

चंडीगढ़, 10 जून 2026:विश्व फैटी लिवर दिवस के अवसर पर पंजाब सरकार ने यकृत संबंधी बीमारियों की रोकथाम, समय पर पहचान और उपचार को लेकर अपने प्रयासों को और तेज करने का संकल्प दोहराया है। राज्य सरकार का मानना है कि तेजी से बढ़ रहा फैटी लिवर रोग अब एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बन चुका है, जिसके प्रभावी नियंत्रण के लिए जागरूकता, नियमित जांच और सुलभ उपचार अत्यंत आवश्यक हैं।

पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि फैटी लिवर रोग एक "साइलेंट महामारी" के रूप में उभर रहा है, क्योंकि अधिकांश मामलों में इसके शुरुआती चरण में कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते। उन्होंने कहा कि यदि समय पर इसकी पहचान और उपचार न किया जाए तो यह बीमारी लिवर में सूजन, फाइब्रोसिस, सिरोसिस और यहां तक कि लिवर फेलियर जैसी गंभीर स्थितियों का कारण बन सकती है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।इसी दिशा में 'मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना' के तहत राज्य के प्रत्येक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है।

पंजाब पुलिस का 'स्टूडेंट पुलिस कैडेट' कार्यक्रम बना युवाओं के सशक्तिकरण का प्रभावी मंच, 11,200 से अधिक विद्यार्थी उठा रहे लाभ

चंडीगढ़, 10 जून 2026:पंजाब पुलिस की 'यूथ कनेक्टिविटी' पहल के अंतर्गत संचालित 'स्टूडेंट पुलिस कैडेट (एसपीसी)' कार्यक्रम को राज्य भर के स्कूलों से व्यापक समर्थन और उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिल रही है। विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, सामाजिक जिम्मेदारी और कानून के प्रति सम्मान विकसित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया यह कार्यक्रम आज युवाओं को सकारात्मक दिशा देने का एक प्रभावी माध्यम बन चुका है। वर्तमान में पंजाब के 280 चयनित स्कूलों के लगभग 11,200 विद्यार्थी इस पहल से लाभान्वित हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा 22 अगस्त 2023 को शुरू किए गए इस कार्यक्रम को पुलिस महानिदेशक गौरव यादव के नेतृत्व में पूरे राज्य में सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत अब तक 1,965 इनडोर और 698 आउटडोर कक्षाएं आयोजित की जा चुकी हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को नागरिक कर्तव्यों, सामाजिक मूल्यों, अनुशासन, नेतृत्व कौशल और पुलिस व्यवस्था की कार्यप्रणाली से अवगत कराया जा रहा है।

मानसा की बुजुर्ग महिला को मिला न्याय, पंजाब सरकार के हस्तक्षेप से आरोपी गिरफ्तार

चंडीगढ़, 10 जून:मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों, सुरक्षा और सम्मान की रक्षा के लिए लगातार सक्रिय कदम उठा रही है। इसी प्रतिबद्धता के तहत सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग ने जिला मानसा की एक बुजुर्ग महिला की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभाग के हस्तक्षेप और संबंधित एजेंसियों के समन्वित प्रयासों से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे पीड़ित महिला को राहत मिली है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि बुजुर्ग महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि पारिवारिक विवाद और संपत्ति से जुड़े मामलों को लेकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है तथा उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। शिकायत प्राप्त होते ही विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया और जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, मानसा को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लें, रोजाना एक घंटा सेहत को दें: स्पीकर संधवां

चंडीगढ़, 10 जून 2026: पंजाब विधानसभा के स्पीकर स. कुलतार सिंह संधवां ने राज्य के लोगों से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा है कि यह योजना आम परिवारों को चिकित्सा आपात स्थितियों के दौरान होने वाले भारी आर्थिक बोझ से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी व्यक्ति को आर्थिक तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहना पड़े।

स्पीकर संधवां ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इस योजना में कैंसर सहित कई गंभीर और जटिल बीमारियों के उपचार को शामिल किया गया है, जिससे जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिल रही है। उन्होंने बताया कि लाभार्थी राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी उपचार प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार का लक्ष्य केवल बीमारियों का उपचार करना ही नहीं, बल्कि लोगों को स्वस्थ और जागरूक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना भी है। इसी सोच के तहत स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ-साथ जनजागरूकता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

संधवां ने कहा कि आधुनिक जीवनशैली और बढ़ते तनाव के कारण अनेक स्वास्थ्य समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे रोजाना कम-से-कम एक घंटा अपने शरीर और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अवश्य निकालें। योग, सुबह की सैर, दौड़, व्यायाम, खेलकूद और जिम जैसी गतिविधियां न केवल शरीर को स्वस्थ रखती हैं, बल्कि मानसिक तनाव को भी कम करती हैं।

उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ व्यक्ति ही अपने परिवार, समाज और कार्यक्षेत्र में बेहतर योगदान दे सकता है। इसलिए स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। स्पीकर ने यह भी कहा कि यदि किसी परिवार ने अभी तक मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पंजीकरण नहीं करवाया है, तो वे जल्द से जल्द अपना स्वास्थ्य कार्ड बनवाएं। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए लोग अपने नजदीकी सेवा केंद्र पर जाकर पंजीकरण करवा सकते हैं।इसके अलावा योजना के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है।

मान सरकार ने 48 जिला सिस्टम मैनेजरों और सहायक सिस्टम मैनेजरों को सौंपे नियुक्ति पत्र, युवाओं को रोजगार देने की

चंडीगढ़, 10 जून:पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार ने राज्य के युवाओं को पारदर्शी और योग्यता आधारित रोजगार उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर मजबूत करते हुए 48 जिला सिस्टम मैनेजरों (डीएसएम) और सहायक सिस्टम मैनेजरों (एएसएम) को नियुक्ति पत्र सौंपे। पंजाब भवन में आयोजित समारोह के दौरान राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सरकारी भर्तियों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है तथा चयन केवल योग्यता के आधार पर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स सोसायटी द्वारा 15 अप्रैल 2025 को जिला सिस्टम मैनेजर और सहायक सिस्टम मैनेजर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। निर्धारित प्रक्रिया के तहत रिकॉर्ड समय में भर्ती पूरी करते हुए 11 जिला सिस्टम मैनेजर और 37 सहायक सिस्टम मैनेजरों का चयन किया गया।

हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि चयनित उम्मीदवारों को जालंधर स्थित डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स कार्यालय में दो माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण में एक माह का राजस्व संबंधी प्रशिक्षण तथा एक माह का फील्ड प्रशिक्षण शामिल होगा, जिससे वे आधुनिक भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली को प्रभावी ढंग से संचालित करने में सक्षम बन सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह भर्ती राज्य में नागरिक सेवाओं को और अधिक कुशल एवं तकनीक आधारित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व की सराहना करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार ने युवाओं के सशक्तिकरण और रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 66 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की जा चुकी हैं, जिससे युवाओं का सरकारी भर्ती प्रणाली पर विश्वास मजबूत हुआ है।

उन्होंने नव-नियुक्त अधिकारियों को ईमानदारी, समर्पण और पेशेवर दक्षता के साथ अपने दायित्व निभाने का आह्वान करते हुए कहा कि भूमि अभिलेख प्रशासन के आधुनिकीकरण और नागरिक-केंद्रित सेवाओं को मजबूत बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने अधिकारियों को किसी भी प्रकार के दबाव या प्रभाव से दूर रहकर जनसेवा की भावना से कार्य करने की सलाह दी।

समारोह को संबोधित करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव-सह-वित्त आयुक्त (राजस्व) अनुराग वर्मा ने कहा कि सभी उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया और योग्यता के आधार पर हुआ है।

herbegy™

Think pure think herbal

PREMIUM SPICES RANGE

Pure Spice. Rich Flavour.

PURE | AROMATIC | PREMIUM QUALITY

Advertisement

For Dealer Inquiry Contact:

727-515-0015

Printed by: Desh Sewak Printers Limited, Sector-29-D, Chandigarh – 160030 and Published by: Shafiur Rahman from #2111 SF, TDI City, Sector-110, Mohali, Sahibzada Ajit Singh Nagar, Punjab – 140307. Owner, Publisher & Chief Editor: Shafiur Rahman. Title Verification Number: PBBIL/26/A0779. Periodicity: Monthly.